

नकली खाद घोटाले पर किरोड़ी मीणा का शिकंजा-दूसरे दिन भी फैक्ट्रियों पर छापेमारी, कर्मचारी ताला लगाकर भागे, 5 यूनिट सीज

अजमेर/किशनगढ़। राजस्थान के कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने किशनगढ़ इलाके में फैले नकली उर्वरक के गोरखधंधे पर सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। लगातार दूसरे दिन शुक्रवार को उन्होंने डोंडवाड़ा, बांदरसिंदरी और चौसला गांव की खाद फैक्ट्रियों पर औचक छापेमारी की। मंत्री की कार्रवाई से हड़कंप मच गया और एक फैक्ट्री में तो कर्मचारी ताला लगाकर मौके से भाग खड़े हुए। किरोड़ी मीणा शुक्रवार सुबह डोंडवाड़ा की राधिका एग्रो फैक्ट्री पहुंचे और फिर बांदरसिंदरी में एक अन्य खाद यूनिट का निरीक्षण किया। यहां से वे चौसला गांव पहुंचे जहां एक फैक्ट्री के कर्मचारियों ने खाद को बाहर फेंका

और फैक्ट्री में ताला लगाकर फरार हो गए। मंत्री ने तुरंत अधिकारियों को फैक्ट्री तुड़वाकर जांच के निर्देश दिए। अब तक की जांच में 5



फैक्ट्रियों को सीज कर दिया गया है। कृषि विभाग ने किशनगढ़ विधानसभा क्षेत्र की 34 फैक्ट्रियों को जांच के लिए चिन्हित किया

है। अधिकारियों की मानें तो इन फैक्ट्रियों में तैयार नकली डीएपी, यूरिया, जिंक सल्फेट, जिप्सम और पोटाश की आपूर्ति सिर्फ राजस्थान के किसानों को नहीं, बल्कि हरियाणा, पंजाब, बिहार जैसे राज्यों में भी की जाती रही है। किरोड़ी मीणा ने गुरुवार को

किशनगढ़ की 12 खाद फैक्ट्रियों में औचक निरीक्षण किया था, जिसके बाद प्रशासन ने रातभर में सबूतों को सुरक्षित कर लिया। शुक्रवार को कार्यवाही और तेज की गई। मंत्री खुद किशनगढ़ में रुके और सुबह से ही अधिकारियों की टीम के साथ निकल पड़े।

जयपुर-अजमेर की संयुक्त टीमों की कार्रवाई

जयपुर और अजमेर की कृषि विभाग की टीमों भी सक्रिय हैं। अजमेर में आत्मा परियोजना की प्रोजेक्ट डायरेक्टर उषा चित्ता ने बताया कि शुक्रवार को उदयपुरकरला की भूमि एगरोटेक्स, गोवर्धन एग्रो और एक अन्य फैक्ट्री तथा टीकावड़ा गांव की दो फैक्ट्रियों को सीज किया गया है। साथ ही

टेम्पो, जेसीबी, ट्रैक्टर जैसी मशीनरी को जब्त किया गया है।

गुरुवार को जिन 12 फैक्ट्रियों की जांच हुई थी, इनमें अतिशय बायोटेक इंडस्ट्रीज लिमिटेड, किशनगढ़, कमला बायो ऑर्गेनिक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड, किशनगढ़, ट्रांफिकल एग्रो सिस्टम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, किशनगढ़, राघव एग्रो इंडस्ट्रीज, किशनगढ़, श्री गोवर्धन एग्रो, किशनगढ़, दिव्या एग्रो फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज, नालू, भूमि एग्रो इंडस्ट्रीज, किशनगढ़, श्रीनाथ एग्रो इंडस्ट्रीज, किशनगढ़, एशिया डोन बायोकेयर, जयपुर, वर्दी जल एग्री टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, अजमेर शामिल हैं। दो अन्य फैक्ट्रियां भी हैं।

मालिकों की तलाश, केस दर्ज की तैयारी

प्रशासन अब इन फैक्ट्रियों के मालिकों की जानकारी इकट्ठा कर रहा है। जल्द ही इनके खिलाफ आपराधिक मुकदमे दर्ज किए जाएंगे। डिप्टी डायरेक्टर (फर्टिलाइजर) नवलकिशोर मीणा के अनुसार, मामले की गंभीरता को देखते हुए बड़ी कार्यवाही तय है। यह कार्रवाई बताती है कि नकली खाद का नेटवर्क न सिर्फ किसानों को लूट रहा था बल्कि पूरे उत्तरी भारत की कृषि प्रणाली के लिए खतरा बन चुका था। मंत्री किरोड़ी मीणा की इस पहल से प्रशासन की नौद टूटी है और कई जिलों में नकली खाद के सौदागरों की शामत आने वाली है।

क्या जेपी नड्डा के दौर से पहले राजस्थान भाजपा में होगा बदलाव?

जयपुर। राजस्थान भाजपा में संभावित संगठनात्मक बदलावों को लेकर जारी अटकलों पर प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने पूर्ण विराम लगा दिया है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आगामी जयपुर दौरे को लेकर भाजपा के सियासी गलियारों में नई टीम के ऐलान की चर्चा जोरों पर थी, लेकिन राठौड़ ने स्पष्ट किया कि इस दौर में संगठनात्मक बदलाव पर कोई बातचीत नहीं होगी। इतिहास में फैलाई गई महाराणा प्रताप को लेकर कई झूठी बातें, राजस्थान के राज्यपाल ने खोली परतें

दरअसल, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि भाजपा में संगठन से जुड़े बदलाव एक निर्धारित प्रक्रिया के तहत होते हैं। इस दौर में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से इस विषय पर कोई चर्चा नहीं होगी। फिलहाल, नई टीम को लेकर कोई आधिकारिक बातचीत तय नहीं है। राठौड़ शुक्रवार को अहिल्याबाई होल्कर की 300वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित होने वाले भव्य कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेने एंटरटेनमेंट पैराडिज (शुक्र) पहुंचे। इस कार्यक्रम में जेपी नड्डा मुख्य वक्ता होंगे।

आपको बता दे, जेपी नड्डा 31 मई को जयपुर में कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे। शुक्रमं आयोजित मुख्य कार्यक्रम में वे अहिल्याबाई होल्कर के जीवन और योगदान पर प्रकाश डालेंगे। महिला कार्यकर्ताओं और जयपुर संभाग के जनप्रतिनिधियों की भारी भागीदारी तय मानी जा रही है। कार्यक्रम के बाद नड्डा का मुख्यमंत्री निवास पर एक और कार्यक्रम रहेगा। फिर रात्रि 10 बजे वे दिल्ली के लिए रवाना होंगे।

व्यवस्थाओं में लापरवाही पर भड़के राठौड़

बताया जा रहा है कि दौरे की तैयारियों के बीच वरिष्ठ भाजपा नेता और पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कार्यक्रम की व्यवस्थाओं में ढिलाई पर कड़ी नाराजगी जाहिर की। एयरपोर्ट से लेकर पार्किंग तक की व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए उन्होंने कहा कि यह पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का दौरा है, इसे हल्के में लेना गंभीर लापरवाही है। राठौड़ ने मौके पर उपस्थित सभी पदाधिकारियों को उनकी जिम्मेदारियों की याद दिलाई और सख्त लहजे में कहा कि हर कार्यकर्ता अपने कार्य को पूरी निष्ठा और गंभीरता से निभाए।

मदन राठौड़ ने स्पष्ट किया कि संगठनात्मक फेरबदल के लिए एक निश्चित प्रक्रिया होती है। उन्होंने कहा कि पहले प्रदेश स्तर पर संभावित टीम की सूची तैयार की जाती है। फिर यह सूची राष्ट्रीय नेतृत्व को भेजी जाती है। इसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष उस पर चर्चा करते हैं और निर्णय लेते हैं। उन्होंने बताया कि इस दौर में ऐसी किसी भी प्रक्रिया की शुरुआत नहीं हो रही है।

दौसा में कोरोना की वापसी, 5 वर्षीय मासूम पॉजिटिव, चिकित्सा विभाग में मचा हड़कंप

दौसा। काफ़ी अरसे बाद कोरोना ने एक बार फिर जिले में दस्तक दी है। एक 5 साल के मासूम को कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद चिकित्सा विभाग में हड़पंच मचा हुआ है। बच्चे के पैर में तकलीफ होने पर परिजन उसे इलाज के लिए अस्पताल लेकर पहुंचे थे, जहां से बच्चे को जेके लोन अस्पताल जयपुर रैफर किया गया था। जांच रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने पर सीएमएचओ को सूचना मिली। इसके बाद जिले के सभी ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही बच्चे की परिवार के अन्य सदस्यों के सैंपल लेने के लिए टीम भेजी गई है। बता दें कि जिले में अंतिम बार कोरोना पॉजिटिव केस जनवरी 2024 में सामने आया था। उस वक एक 22 दिन की बच्ची को कोरोना पॉजिटिव घोषित किया गया था। जिसका जन्म 19 दिसम्बर 2024 को महिला चिकित्सालय जयपुर में हुआ था।

शाहपुरा तहसील कार्यालय में पटवारी 1500 रुपये की रिश्त लेते रंगे हाथ गिरफ्तार

शाहपुरा। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) भीलवाड़ा-प्रथम की टीम ने शुक्रवार को शाहपुरा तहसील कार्यालय में पटवारी बबलू धोबी को 1500 रुपये की रिश्त लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया। आरोपी पटवारी, पटवार हल्का लसाडिया में तैनात है। जानकारी के अनुसार, परिवारी दे, एकको शिकायत दी थी कि वह अपने दिवंगत पिता की लसाडिया स्थित 6 बीघा ज़मीन (खसरा नंबर 291, 414, 535) का वारिसाना नामांतरण करवाना चाहता था। इस प्रक्रिया के लिए पटवारी बबलू धोबी ने दस्तावेज़ ऑनलाइन कराने और आगे की कार्रवाई के बदले 2000 की रिश्त मांगी। शिकायत का सत्यापन 22 अप्रैल 2025 को किया गया, जिसमें पटवारी द्वारा 7500 की रिश्त ले गई थी। शेष 71500 की राशि आज 30 मई को शाहपुरा तहसील कार्यालय में लेते समय, एकटीम ने उसे ट्रेप कर पकड़ा। एकमहानिदेशक डॉ. रवि प्रकाश मेहरड़ा ने बताया कि कार्यवाही अजमेर रेंज के उपमहानिरीक्षक कालूराम रावत के पर्यवेक्षण में की गई। कार्रवाई का नेतृत्व, एक भीलवाड़ा-प्रथम की पुलिस निरीक्षक कल्पना ने किया। आरोपी के पैट की जेब से रिश्त की राशि बरामद की गई।

एककी अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस राजेश सिंह के सुपरविजन में आगे की पूछताछ व कानूनी कार्यवाही जारी है। आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर आगे की जांच की जा रही है।

परिवहन सेवाओं में सुधार के लिए अन्य राज्यों का करें अध्ययन-भजनलाल शर्मा

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार परिवहन व्यवस्था को अधिक सुदृढ़, सुरक्षित एवं सुविधायुक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। भविष्य की आवश्यकताओं को देखते हुए लक्ष्य निर्धारित कर कार्ययोजनाओं को धरातल पर उतारा जा रहा है। उन्होंने कहा कि राजस्थान रोडवेज की बसों में ऐसी सुविधाएं उपलब्ध कराएं, जिससे कार वाले भी बसों में यात्रा के लिए प्रेरित हों।

शर्मा शुक्रवार को मुख्यमंत्री निवास पर परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग और राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने रोडवेज चालक, परिचालक सहित सभी कार्मिकों के लिए प्रशिक्षण सेमिनार आयोजित कराने के निर्देश दिए। इसमें रोडवेज बस सुविधाओं के आधुनिकीकरण, सुव्यवस्थित परिवहन में सबकी भागीदारी, स्वच्छता और नियमों की पालना जैसे विषयों की विस्तृत जानकारी दी जाए। उन्होंने रोडवेज बस स्टैंड और विश्राम स्थलों पर सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने और उन्हें एक ही रंग में विकसित करने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पथ परिवहन निगम भविष्य को देखते हुए सुविधाओं का विस्तार करें। सुरक्षित सफर के साथ बसों में भोजन और सरस उत्पाद उपलब्ध कराने का नवाचार किया जाए। उन्होंने प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों के लिए समर्पित रूट बनाकर बसों का समयबद्ध संचालन कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बसों में कैमरे और जीपीएस स्थापित करें। लोक परिवहन बसों का भी कलर निर्धारण किया जाए। नए बसों के पंजीकरण से पहले उनकी बॉडी की गुणवत्ता जांच भी अनिवार्य की जाए।

सख्त कार्रवाई और कड़ी निगरानी के निर्देश-

शर्मा ने पद दुरुपयोग करने वाले कार्मिकों, ओवरलोड और ओवरस्पीड वाहन चालकों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई और निगरानी के निर्देश दिए। अधिकारियों ने अवगत कराया कि ट्रांसपोर्ट व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग एंड इमरजेंसी अलर्ट सिस्टम के कमांड एंड कंट्रोल रूम की शीश्र शुरूआत की जाएगी। साथ ही, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के



राजधरा एप से बसों के रूट्स का डिजिटलाइजेशन भी जल्द करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि नवीन परमिट जारी करने से पहले रूट निर्धारण करें, जिनमें अस्पताल, शैक्षणिक संस्थान, राजकीय कार्यालयों का विशेष ध्यान रखा जाए। नई बसों की खरीद व संचालन समयबद्ध सुनिश्चित कराएं। राजस्थान व्हीकल स्क्रेप पॉलिसी शीश्र लागू की जाए तथा ऑटोमैटिक टैस्टिंग स्टेशन भी आरंभ किए जाएं। श्री शर्मा ने कहा कि सुव्यवस्थित परिवहन सेवाओं के लिए देश के अन्य राज्यों का अध्ययन कराएं। विशेषज्ञों से भी सुझाव आमंत्रित किए जाएं।

शर्मा ने कहा कि सड़क सुरक्षा हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। सभी को परिवहन नियमों की पालना करनी चाहिए, तभी सड़क दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने और सार्वजनिक परिवहन को अधिक सुविधाजनक बनाने में इलेक्ट्रिक वाहनों की महत्वपूर्ण भूमिका है। इस दौरान उप मुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा सहित सम्बंधित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

प्रस्तावित एलिवेटेड रोड से पहले हटेंगे अतिक्रमण, जेडीए ने चिह्नित किए 156 कब्जे

जयपुर। सांगानेर फ्लाईओवर से न्यू सांगानेर रोड और डिग्गी-मालपुरा रोड तक प्रस्तावित एलिवेटेड रोड के निर्माण कार्य से पहले सड़क पर हुए अतिक्रमण हटाए जाएंगे।

जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) अधिकारियों के अनुसार, 156 अतिक्रमण चिह्नित किए जा चुके हैं, जिन्हें पहले चरण में हटाने की कार्रवाई की जाएगी। मुख्य सड़क के दोनों ओर 15-15 फीट तक अतिक्रमण पाया गया है। अधिकारियों का कहना है कि यह कार्रवाई एलिवेटेड रोड निर्माण की पूर्व तैयारी का अहम हिस्सा है।

सांगानेर पुलिया से सांगा सेतु तक 100 फीट और वहां से



चौड़ी सड़क मास्टर प्लान में प्रस्तावित है, जबकि वर्तमान में सड़क की चौड़ाई केवल 60 से 70 फीट है। यही कारण है कि अनिवार्य हो गया है। पहले कर चुका ये बड़ी कार्रवाई -जून 2024-वंदे मातरम मार्ग

अब बॉर्डर की सुरक्षा होगी मजबूत, राजस्थान पुलिस को मिला पहला ड्रॉन पायलट इंस्ट्रक्टर

जयपुर। राजस्थान पुलिस ने ड्रॉन तकनीक के क्षेत्र में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। इंटेलीजेंस ट्रेनिंग अकादमी (आईटीए), जयपुर में तैनात रमेश शर्मा ने भारत सरकार के नागर विमानन महानिदेशालय (छतछ) द्वारा आयोजित रिमोट पायलट इंस्ट्रक्टर कोर्स को पहले ही प्रयास में पास कर इतिहास रच दिया है। इस उपलब्धि के साथ रमेश शर्मा राजस्थान पुलिस के पहले ड्रॉन इंस्ट्रक्टर बन गए हैं, जो सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा और निगरानी को और मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। बता दें, महानिदेशक पुलिस, इंटेलीजेंस संचय अग्रवाल के निर्देशों के तहत यह पहल की गई थी। राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों में बढ़ती ड्रॉन गतिविधियों को देखते हुए आईटीए

जयपुर में एक ड्रॉन रिसर्च सेंटर और ड्रॉन फॉरेंसिक लैब स्थापित करने का उद्देश्य है। इसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आईटीए सेल के प्रभारी रमेश शर्मा को इस विशिष्ट रिमोट पायलट इंस्ट्रक्टर कोर्स के लिए भेजा गया था। रमेश शर्मा के अथक परिश्रम और समर्पण ने उन्हें इस अत्यंत कठिन परीक्षा में सफलता दिलाई। यह विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि डीजीसीए (छतछ) द्वारा आयोजित इस परीक्षा का परिणाम मात्र 22ब रहा है, जो उनकी उपलब्धि को और भी खास बनाता है। यह दिखाता है कि उन्होंने



कितनी कुशलता और ज्ञान के साथ यह कोर्स पूरा किया है। रिमोट पायलट इंस्ट्रक्टर कोर्स क्या है? आईटीए, जयपुर की अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शालिनी सक्सेना ने बताया कि यह कोर्स ड्रॉन पायलटों को प्रशिक्षण देने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसमें शिक्षण कौशल, हवाई नियम-कानून, ड्रॉन संचालन, उड़ान यांत्रिकी, सुरक्षा प्रक्रियाएं और जोखिम प्रबंधन जैसे विषय शामिल हैं। इस कोर्स को पूरा करने वाला व्यक्ति ड्रॉन के सुरक्षित और प्रभावी संचालन के लिए दूसरों को प्रशिक्षित करने में सक्षम होता है। भारत में रिमोट पायलट इंस्ट्रक्टर बनने के लिए डीजीसीए द्वारा मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संगठन से यह कोर्स करना अनिवार्य है।

जयपुर में एक ड्रॉन रिसर्च सेंटर और ड्रॉन फॉरेंसिक लैब स्थापित करने का उद्देश्य है। इसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आईटीए सेल के प्रभारी रमेश शर्मा को इस विशिष्ट रिमोट पायलट इंस्ट्रक्टर कोर्स के लिए भेजा गया था।

रमेश शर्मा के अथक परिश्रम और समर्पण ने उन्हें इस अत्यंत कठिन परीक्षा में सफलता दिलाई। यह विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि डीजीसीए (छतछ) द्वारा आयोजित इस परीक्षा का परिणाम मात्र 22ब रहा है, जो उनकी उपलब्धि को और भी खास बनाता है। यह दिखाता है कि उन्होंने

निकाली है, जो राष्ट्रप्रेम और समर्पण का प्रतीक है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के नेता डोटसरा है, जिनका राष्ट्र के प्रति स्वाभिमान अभी जागृत नहीं हुआ। देश के मामले में राष्ट्र प्रथम की भावना सभी के मन में होनी चाहिए। आतंक के खिलाफ भारत की इस जंग में देश एकजुट है और विपक्ष को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा होना चाहिए।

राष्ट्र के प्रति डोटसरा का अभी जागृत नहीं हुआ स्वाभिमान, इस घड़ी में राष्ट्र के साथ खड़ा होना चाहिए विपक्ष-मदन राठौड़

जयपुर। जयपुर की टोंक रोड स्थित वाटिका क्षेत्र में शुक्रवार को भव्य क्रिसदूर तिरंगा यात्रा निकाली गई। यात्रा में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने शामिल हुए। राठौड़ के साथ पूर्व सांसद रामचरण बोहरा, सरकार के मंत्री झाबर सिंह खर्वा, बागक विधायक डॉ. कैलाश वर्मा, स्टेफो चौहान, अपूर्वा सिंह, जिला प्रमुख

रमा चौपड़ा सहित बड़ी संख्या में महिलाएं, युवतियां और स्थानीय नागरिक, जनप्रतिनिधिगण, मौजूद रहे। सभी ने हाथों में तिरंगा लिए देश की अखंडता, सुरक्षा और एकता का संदेश दिया। महिलाओं ने भारत माता की जय और वंदे मातरम् के जयघोष के साथ यात्रा निकाली। सिंदूर तिरंगा यात्रा में महिलाओं का उत्साह देखने लायक



था। देशभक्ति गीतों और नारों से वातावरण गुंज उठा वाटिका क्षेत्र में आयोजित इस यात्रा को लेकर

सिंदूर की सफलता ने यह दिखा दिया है कि भारत की सेना न केवल अपने नागरिकों की रक्षा में सक्षम है, बल्कि आतंक के अड्डों को नस्तानबूद करने में भी पूरी तरह सक्षम है। पहलगाय में हमारी बहनों पर हुए हमले का जिस तरह से जवाब भारतीय सेना ने दिया है, वह गर्व की बात है। इसी गौरव और सम्मान को आगे बढ़ते हुए बहनों ने सिंदूर तिरंगा यात्रा

निकाली है, जो राष्ट्रप्रेम और समर्पण का प्रतीक है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के नेता डोटसरा है, जिनका राष्ट्र के प्रति स्वाभिमान अभी जागृत नहीं हुआ। देश के मामले में राष्ट्र प्रथम की भावना सभी के मन में होनी चाहिए। आतंक के खिलाफ भारत की इस जंग में देश एकजुट है और विपक्ष को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा होना चाहिए।

पैसिव स्मोकिंग भी बन रही है मौत का कारण

(लेखिका- श्वेता गोयल) (अंतर्राष्ट्रीय तम्बाकू निषेध दिवस 31 मई पर विशेष)

करीब दस प्रतिशत व्यक्ति तो ऐसे होते हैं, जो खुद धूम्रपान नहीं करते लेकिन पैसिव स्मोकिंग के शिकार बनते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन का अनुमान है कि यदि दुनियाभर में धूम्रपान की लत इसी रफ्तार से बढ़ती रही तो आगामी एक-दो वर्षों तक ही धूम्रपान की वजह से 50 करोड़ से भी ज्यादा लोग मारे जा चुके होंगे और अगले 30 वर्षों में केवल गरीब देशों में ही धूम्रपान से मरने वालों की संख्या प्रतिवर्ष 10 लाख से बढ़कर 70 लाख तक पहुँच जाएगी। संगठन का अनुमान है प्रतिवर्ष विश्वभर में 8000 से अधिक नवजात शिशु धूम्रपान के कारण असमय काल के बास बन जाते हैं। आंकड़ों से पता चलता है कि सभी प्रकार के कैंसर में से करीब 40 फीसदी का कारण धूम्रपान ही होता है।

बचपन से ही हम पढ़ते-सुनते आए हैं कि धूम्रपान तथा तंबाकू उत्पाद स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं और शरीर में कैंसर तथा कई अन्य बीमारियों को जन्म देते हैं लेकिन यह जानने-समझने के बाद भी जब हम अपने आसपास किशोरवयु बच्चों को भी धूम्रपान करते और विभिन्न तंबाकू उत्पादों का सेवन करते देखते हैं तो स्थिति काफी चिंताजनक प्रतीत होती है। दरअसल ऐसे किशोरों के मनोमस्तिष्क में धूम्रपान को लेकर कुछ गलत धारणाएँ विद्यमान होती हैं, जैसे धूम्रपान से उनके शरीर में चुस्ती-फुर्ती आती है, उनका मानसिक तनाव कम होता है, मन शांत रहता है, व्यक्ति आकर्षक बनता है, कब्जा की शिकायत दूर होती है आदि-आदि। तमाम वैज्ञानिक शोधों के बावजूद ऐसे व्यक्ति समझना ही नहीं चाहते कि धूम्रपान करने से उनके अंदर ऐसी कोई ताकत नहीं पैदा नहीं होने वाली कि देखते ही देखते वो किसी ऊँचे पर्वत पर छलांग लगा सकें या महाबली हनुमान की भाँति समुद्र लांघ जाएँ। वास्तविकता यही है कि धूम्रपान एक ऐसा धीमा जहर है, जो धीमे-धीमे इसका सेवन करने वाले व्यक्ति का दम घोटता है। धूम्रपान शरीर में धीरे-धीरे प्राणघातक बीमारियों को जन्म देता है और ऐसे व्यक्ति को धीमी गति से मृत्यु शैया तक पहुँचा देने का माध्यम बनता है। तम्बाकू सेवन के व्यापक प्रसार और नकारात्मक स्वास्थ्य प्रभावों को और ध्यान आकर्षित करने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष 31 मई को 'विश्व तम्बाकू निषेध दिवस' मनाया जाता है, जो इस वर्ष तंबाकू उत्पादों के दुष्प्रभावों से भविष्य की पीढ़ियों की रक्षा करने के उद्देश्य से 'अपील का पर्दाफाश- तंबाकू और निकोटीन उत्पादों पर उद्योग की रणनीति को उजागर करना' थीम के साथ मनाया जा रहा है। एक ओर जहाँ विकासशील देशों में धूम्रपान का प्रचलन बढ़ रहा है, वहीं अमेरिका सरीखे कुछ विकसित देशों में धूम्रपान के प्रचलन में तेजी से गिरावट आई है। 1965 में अमेरिका की 42 फीसदी आबादी धूम्रपान की आदी थी जबकि 1991 में यह संख्या घटकर 26 फीसदी रह गई और पिछले डेढ़ दशक में तो वह धूम्रपान करने वालों की संख्या में और भी तेजी से गिरावट आई है। गहराई में जाने पर पता चलता है कि अमेरिका में सिगरेट की खपत में लगातार कमी आने की

वजह से अमेरिका की सिगरेट कम्पनियों ने अपने घाटे की पूर्ति के लिए अपने उत्पादों को भारत तथा अन्य विकासशील देशों में खपाने की योजना बनाई और उसे इस कार्य में सफलता भी मिली। भारत में प्रतिदिन धूम्रपान से मरने वालों की संख्या सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों के मुकाबले 20 गुना है जबकि एड्स से देश में जितनी मौतें 10 वर्ष में होती हैं, उतनी मौतें धूम्रपान की वजह से मात्र एक सप्ताह में ही हो जाती हैं। करीब दस प्रतिशत व्यक्ति तो ऐसे होते हैं, जो खुद धूम्रपान नहीं करते लेकिन पैसिव स्मोकिंग के शिकार बनते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन का अनुमान है कि यदि दुनियाभर में धूम्रपान की लत इसी रफ्तार से बढ़ती रही तो आगामी एक-दो वर्षों तक ही धूम्रपान की वजह से 50 करोड़ से भी ज्यादा लोग मारे जा चुके होंगे और अगले 30 वर्षों में केवल गरीब देशों में ही धूम्रपान से मरने वालों की संख्या प्रतिवर्ष 10 लाख से बढ़कर 70 लाख तक पहुँच जाएगी। संगठन का अनुमान है प्रतिवर्ष विश्वभर में 8000 से अधिक नवजात शिशु धूम्रपान के कारण असमय काल के बास बन जाते हैं। आंकड़ों से पता चलता है कि सभी प्रकार के कैंसर में से करीब 40 फीसदी का कारण धूम्रपान ही होता है। धूम्रपान करने वालों को धूम्रपान न करने वालों की अपेक्षा फेफड़ों का कैंसर होने की संभावना 15 गुना अधिक होती है।

नशे के दुष्प्रभावों पर छपी पुस्तक 'मौत को खुला निमंत्रण' में बताया गया है, 'सिगरेट के धुएँ में करीब 4000 घातक रासायनिक तत्व विद्यमान होते हैं, जिनमें पोलिनियम 210, कार्बन मोनोक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, निकल, पाईरीडिन, बेंजीपाइरीन, नाइट्रोजन आइसोप्रोनावाइड, अम्ल, शार, निकोटीन, टार, जिंक, हाइड्रोजन साइनाइड, कैडमियम, ग्लायकोलिक एसिड, सक्सीनिक एसिड, एसिटिक एसिड, फार्मिक एसिड, मिथाइल क्लोराइड इत्यादि प्रमुख हैं, जो मानव शरीर पर तरह-तरह से दुष्प्रभाव डालते हैं। धूम्रपान से हृदय रोग, लकवा, ह्रद प्रकाश का कैंसर, मोतियाबिंद, कणुसकता, बांझपन, पेट का अल्सर, एसीडिटी, दमा, ब्रोंकाइटिस, मिरगी, मेनिया, स्कीजोफ्रेनिया जैसे घातक रोगों का खतरा भी कई गुना बढ़ जाता है। धूम्रपान से मोतियाबिंद का खतरा बन जाता है और आंख की रेटिना प्रभावित होने लगती है, जिससे नेत्रच्युति कम होती जाती है। गर्भवती महिलाओं द्वारा धूम्रपान किए जाने से कम लम्बाई और कम वजन के बच्चों का जन्म,



बच्चों में अपंगता तथा बाल्यावस्था में ही घातक हृदय रोग जैसी बीमारियों का खतरा काफी बढ़ जाता है। एक अध्ययन के अनुसार प्रतिदिन 20 सिगरेट तक पीने वाली गर्भवती महिला के बच्चे की मृत्यु होने की संभावना सामान्य से 20 प्रतिशत बढ़ जाती है जबकि 20 से अधिक सिगरेट पीने पर यह खतरा 35 प्रतिशत तक हो जाता है। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के अनुसार किसी दूसरे के धूम्रपान के धुएँ के प्रभाव से दिल के दौर से होने वाली मौतों की आंशका 30 प्रतिशत बढ़ जाती है।' विभिन्न सर्वेक्षणों के अनुसार माना गया है कि विकसित देशों में 41 फीसदी पुरुष और 21 फीसदी स्त्रियाँ धूम्रपान करती हैं जबकि विकासशील देशों में सिर्फ 8 फीसदी स्त्रियों को इसकी लत लगी है तथा पुरुषों की संख्या 50 फीसदी से भी अधिक है।

जहाँ तक हमारे यहाँ सिगरेट के पैकेटों पर लिखी वैधानिक चेतावनी का सवाल है तो यह कितनी असरकारक है, इससे कोई अपरिचित नहीं है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार प्रतिदिन एक पैकेट सिगरेट पीने वाला व्यक्ति अपने जीवन के 8 दिन कम कर लेता है, इसलिए सिगरेट के पैकेटों से वर्तमान वैधानिक चेतावनी को हटाकर यह लिख दिया जाना चाहिए कि इस पैकेट के उपयोग से आपके जीवन के 8 दिन कम हो जाएंगे। बहरहाल, तमाम स्वास्थ्य विशेषज्ञों और शोधों का एक स्वर में यही कहना है कि धूम्रपान एक अत्यंत धीमा किन्तु प्राणघातक विष है, इसलिए स्वयं तो धूम्रपान से बचें ही, धूम्रपान के आदी लोगों को भी इस लत को छोड़ने के लिए प्रेरित करें।

(लेखिका डेढ़ दशक से शिक्षण क्षेत्र से जुड़ी हैं)

संपादकीय

डेल्टा की घातकता

हाल के वर्षों में उन तमाम घटनाओं ने हर आम भारतीय को विचलित किया, जिसमें हमने लोगों को खेलते वक, दफ्तर में काम करते समय, मंच पर नृत्य करते अचानक बेहोश होकर गिरते देखा। इसे साइलेंट हार्ट अटैक के रूप में देखा गया। तुरंत-फुरत अस्पताल ले जाने के बाद पता चला कि उस व्यक्ति की तो मृत्यु हो चुकी है। तब कुछ लोगों ने वैकसीन के दुष्प्रभावों का जिक्र किया, लेकिन कोई अंतिम निष्कर्ष सामने नहीं आया। लेकिन अब एक भारतीय शोध में इस अचानक दिल की धड़कन बंद होने की वजह का पता लगाने का दावा किया गया है। यह तथ्य आईआईटी इंदौर और आईसीएमआर के सहयोग से किए गए नये शोध में सामने आया है। शोध बताता है कि कोविड-19 का डेल्टा वैरिएंट पिछले दिनों की साइलेंट हार्ट अटैक की घटनाओं की वजह बना है। साथ ही कुछ लोगों में थायरॉइड के अनियंत्रित होने की वजह भी इसी वैरिएंट को बनाया गया है। बताया जाता है कि हाल ही में, यह शोध 'जर्नल ऑफ प्रोटिओम रिसेच' में प्रकाशित हुआ है। यह खुलासा ऐसे समय में हो रहा है जब कोविड-19 के एक नये वैरिएंट ने एशिया और अमेरिकी देशों में लोगों को अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया है। भारत में भी कुछ मौतों के साथ इसके संक्रमण के बढ़ते मामले दर्ज किए जा रहे हैं। दरअसल, आईआईटी इंदौर और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के साझे प्रयास से हुए शोध में 3134 मरीजों के जुटाए डेटा का उपयोग करके इसे अंजाम दिया गया। जिसमें कोविड-19 को पहली और दूसरी लहर के दौरान मूल वैरिएंट, अल्फा, बीटा, गामा व डेल्टा वैरिएंट से संक्रमित रोगियों के शरीर के रसायनों में विभिन्न बदलावों से जुड़े डेटा का विश्लेषण किया गया। इसमें शारीरिक रसायनों में आए बदलाव के साथ ही स्पाइक प्रोटीन के संपर्क में आने वाले फेफड़ों और कोलन सेल का भी विश्लेषण किया गया। हालिया शोध में शोधकर्ता इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि डेल्टा वैरिएंट ने हार्मोन संतुलन बिगाड़ने में बड़ी भूमिका निभायी। दरअसल, शोध में पाया गया कि डेल्टा वैरिएंट के चलते मानव शरीर में रासायनिक असंतुलन पैदा हुआ था। फलतः कैंटेकोलामाइन और थायरॉइड हार्मोन पैदा करने की प्रक्रिया में अवरोध उत्पन्न हुआ। जिसकी वजह से कोविड से उबरने वालों में कालांतर साइलेंट हार्ट अटैक और थायरॉइड में व्यवधान की स्थितियाँ पैदा हुईं। इसी हालिया अध्ययन में यह भी खुलासा हुआ कि कोरोना के शिकार हुए लोगों में स्वस्थ होने के बावजूद, उनके शरीर में यूरिया और अमीनो एसिड मेटाबोलिज्म में व्यवधान होने की पुष्टि भी हुई है। दरअसल, अचानक होने वाली मौतों, जिसे आमतौर पर साइलेंट हार्ट अटैक कहा जाता है, में वे लक्षण नहीं दिखाई देते जो सामान्यतः हार्ट अटैक होने पर नजर आते हैं। मसलन बेचेनी, पसीना आना, सीने में दर्द होना और सांस फूलने जैसे लक्षण दिखाई नहीं दिए। इसमें व्यक्ति कटे पेड़ की तरह अचानक नीचे गिर जाता है, जब तक उसके उपचार की कोशिश होती है तब तक पता चलता है कि उसकी मृत्यु हो चुकी है। दरअसल, यह स्थिति कार्डियक अरेस्ट से भिन्न है, जिसमें दिल की धड़कन बंद होती है। चिकित्सक इस स्थिति से बचाव के लिये नियमित आधे घंटे टहलने, गर-संक्रामक रोगों मसलन उच्च रक्तचाप व मधुमेह पर नियंत्रण, तली-भुनी चीजों व डिब्बाबंद खाद्य पदार्थों से परहेज, सिगरेट-शराब से तोबा करने की सलाह दे रहे हैं। साथ ही साइलेंट हार्ट अटैक आने पर उसे तुरंत कार्डियो पल्मोनरी रिसीसिटेशन यानी सीपीआर देने की राय दे रहे हैं। जिसे लगातार देने से जान बचाने की कोशिश की जा सकती है। जिसको लेकर समाज में जागरूकता अभियान चलाने की भी जरूरत है, क्योंकि रोगी की जान बचाने में सहायक साबित हो सकता है।

महारानी अहिल्याबाई होलकर

(लेखक- शिवप्रकाश / ईएमएस)

पुण्यश्लोक महारानी अहिल्याबाई होलकर 31 मई 1725 को अहमदनगर (अहिल्या नगर) के नाम से प्रसिद्ध जनपद के चौड़ी गांव में जन्मी थी। यह वर्ष उनके जन्म का त्रिशताब्दी वर्ष है। उनके सुशासन, लोक कल्याणकारी नीतियों एवं आसेतु हिमालव सांस्कृतिक उत्थान के कार्यों को जन-जन तक पहुंचाने के लिए उनका 300 वीं जयंती वर्ष संपूर्ण देश मना रहा है। समाज जीवन में सक्रिय अनेक सामाजिक संगठनों ने इस कार्य को बड़े उत्साहपूर्वक संपन्न किया है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी के नेतृत्व में 21 मई से 31 मई तक 10 दिवसीय अभियान लोकमाता अहिल्याबाई की स्मृति को समर्पित किया है। महारानी अहिल्याबाई होलकर के बहुआयामी व्यक्तित्व एवं उनके प्रेरणा प्रद जीवन से प्रेरित प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण की योजनाओं एवं ऋविकास से विरासत के उनके संकल्प को जन-जन तक पहुंचाने का काम भाजपा के कार्यकर्ता कर रहे हैं। बौद्धिक संवाद, प्रदर्शनी, छात्र-छात्राओं के बीच प्रतियोगिताएँ, मंदिरों व घाटों की स्वच्छता, आरती एवं शोभायात्राओं के माध्यम से यह कार्य संपन्न हो रहा है। राज्यों की सरकारें एवं स्थानीय प्रशासन द्वारा भी अनेक योजनाओं एवं संस्थाओं का नाम महारानी अहिल्याबाई होलकर के नाम पर किया गया है।

पश्चिमी विद्वानों ने भारत के संबंध में दुष्प्रचार करते हुए कहा कि 'हिन्दु शासन व्यवस्था अराजक थी', जेम्स मिल ने लिखा था कि 'भारत नैतिक रूप से खोखला और स्वार्थी समाज था जो शासन योग्य नहीं था'। जबकि पश्चिमी देशों में धर्म के नाम पर भीषण अत्याचार हो रहे थे। तब भारत में महारानी अहिल्याबाई होलकर ने लोक कल्याणकारी धर्मराज्य की स्थापना की थी।

भारत में धर्म एक व्यापक कल्पना है। धर्म व्यक्तिगत जीवन में अर्थोपार्जन एवं मानवीय गुणों के विकास से लेकर मोक्ष तक का मार्ग सिखाता है।

वही शासनकर्ताओं के लिए आर्थिक समृद्धि को बढ़ाने वाली नीतियों एवं योजनाओं तथा व्यक्तिगत जीवन में परस्पर आत्मीय व्यवहार, समाज, प्रकृति आदि के साथ अपना संबंध सिखाता है। इसी को ऋषि कणाद द्वारा वैशेषिक सूत्र में कहा गया है कि :

'यतो अयुदय निःश्रेयस सिद्धिः स धर्मः'

जो समाज में अयुदय (भौतिक उन्नति), निश्रेय (आध्यात्मिक उन्नति) सिखाता है वही धर्म है।

भारत में धर्म के आधार पर चलने वाले शासन को ही आदर्श शासन माना गया है। जिसमें सभी सुखी एवं निरोगी हो। अर्थात् भौतिक दृष्टि से आर्थिक समृद्ध, सभी को स्वस्थ जीवन प्रदान करने वाली नीतियों, परस्पर प्रेम, भय रहित वातावरण, सभी अपने धार्मिक कर्तव्यों का पालन कर सकें ऐसा वातावरण ही आदर्श राज्य का उदाहरण बना। ऐसा योग्य शासन प्रभु श्री राम ने दिया, इसलिए रामराज्य सभी के लिए आदर्श एवं अनुकरणीय राज्य हो गया। रामराज्य के इसी आदर्श का पालन करने का प्रयास सम्राट विक्रमादित्य, राजा भोज, सम्राट हर्षवर्धन जैसे अनेक राजाओं ने किया। विदेशी आक्रमणों के समय इन्हीं मूल्यों की रक्षा करने के लिए महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज सरीखे शासनकर्ताओं ने अपने प्राण को न्योछावर कर दिया। 300 वर्ष पूर्व महारानी अहिल्याबाई होलकर भी इन्हीं शाश्वत मूल्यों का पालन करने वाली महारानी थीं।

महारानी अहिल्याबाई ने अपने ससुर की मृत्यु के पश्चात 1967 में मालवा राज्य का शासन संभाला। नर्मदा के प्रति भक्ति, व्यावसायिक एवं सामरिकता से उन्होंने अपनी राजधानी नर्मदा के तट पर महेश्वर को बनाया। 28 वर्ष उन्होंने अपनी मृत्यु पर्यन्त यह शासन सत्ता संभाली। किसानों के विकास की योजनाएँ, भूमिहीन किसानों को भूमि प्रदान करना, जनजातों के विकास, अपने शासन को अपराध मुक्त करना, रोजगारपरक अर्थनीति, महिला सशक्तिकरण उसके लिए महेश्वरी साड़ी का निर्माण एवं सैनिक कल्याण उनके शासन की विशेषताएँ थीं। 500 महिलाओं की सैनिक टुकड़ी का निर्माण कर एक महिला फौज भी उन्होंने तैयार की थी। महेश्वर साड़ी आज भी उनकी है।

(चिंतन-मनन)



किसी संत के पास एक युवक आया और उसने उनसे धर्म ज्ञान देने की प्रार्थना की। संत ने कहा कि वह उनके साथ कुछ दिन रहे, फिर वे उसे धर्म का सार बताएंगे। युवक उनके आश्रम में रहने लगा। वह संत की हर बात मानता और उनकी सेवा करता। इस तरह कई दिन बीत गए। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि संत उसे धर्म के बारे में कब बताएंगे। वह उनसे धर्म की चर्चा करने के लिए उत्सुक था।

वह चाहता था कि उनसे शिक्षा प्राप्त कर घर लौट

जाए पर संत कुछ खास कह ही नहीं रहे थे। युवक का वैयर्थ जवाब दे रहा था। एक दिन उसने पूछ ही दिया-मुझे आप इतने दिन हो गए पर अब तक आपने मुझे धर्म का सार नहीं बताया। आखिर मैं कब तक प्रतीक्षा करूँ? संत ने हंसकर कहा-कैसी बात कर रहे हो। तुम जिस दिन से मेरे साथ रह रहे हो उस दिन से मैं तुम्हें धर्म का सार बता रहा हूँ। पर तुम ध्यान ही नहीं दे रहे। युवक ने चौंकर कहा-वो कैसे? संत बोले- जब तुम मेरे लिए पानी लाते हो, मैं

उसे सदैव प्रेम से स्वीकार करता हूँ। तुम्हारे प्रति आभार भी प्रकट करता हूँ। जब-जब तुमने मुझे आदरपूर्वक प्रणाम किया, मैंने तुम्हारे साथ नम्रता का व्यवहार किया। यही तो धर्म है जो हमारे दैनंदिन व्यवहार में झलकता है। धर्म कोई पुस्तकीय ज्ञान नहीं है। तुम मेरे और कार्यों पर गौर करो। मैं लोगों से कैसे मिलता हूँ और किस तरह उनकी सहायता करता हूँ। इससे अलग कुछ भी धर्म नहीं है। युवक संत का आशय समझ गया।

विचार मंचन

(लेखक- सनत जैन)

भारत के लोकतंत्र की आत्मा संसद है संसद की प्रशासनिक रीढ़ उसका सचिवालय और निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं। संविधान के अनुच्छेद 98 में स्पष्ट रूप से लोकसभा और राज्यसभा के लिए स्वतंत्र सचिवालय सेवा की स्थापना, कर्मचारियों की नियुक्ति, प्रक्रिया और प्रशासनिक स्वायत्तता सुनिश्चित करता है। यह प्रावधान संसद को कार्यपालिका से स्वतंत्र बनाए रखने के उद्देश्य से किया गया था। पिछले दो दशकों से, इस संवैधानिक भावना एवं नियमों की खुली अवहेलना हो रही है। जिसके कारण संवैधानिक अधिकारों की रक्षा संभव नहीं हो पा रही है। लोकसभा और राज्यसभा के

महासचिव जैसे सर्वोच्च प्रशासनिक पदों पर सचिवालय का उल्लंघन करते हुए अब भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) या भारतीय राजस्व सेवा (आईआरएस) के अधिकारियों की नियुक्तियाँ इस बात का प्रमाण हैं। यह पद संसदीय सचिवालय सेवा के वरिष्ठतम अधिकारियों के लिए सुरक्षित माने जाते थे। सचिवालय के सारे अधिकार लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा में सभापति के अधीन होते हैं। अब यहपरंपरा और अधिकार एक तरह से समाप्त होना जा रहा है। यह केवल एक प्रशासनिक मुद्दा नहीं है। बल्कि लोकतंत्र के स्तंभों की स्वतंत्रता के सिद्धांत को समाप्त करते हुए, सीधे-सीधे सचिवालय का उल्लंघन है। पूर्व में संसद सचिवालय सेवा से जुड़े विद्वान अधिकारी जैसे सुभाष कश्यप या योगेंद्र

नारायण जैसे अधिकारियों ने इन पदों की गरिमा को स्थापित किया। सचिवालय और सांसदों के अधिकारों की रक्षा करते हुए नियम और कानूनों को बनाने में बेहतर योगदान दिया। जिसके कारण भारत की संसदीय परंपरा सारी दुनिया में स्थापित हुई। सारी दुनिया में सचिवालय और लोकतांत्रिक परंपराओं को लेकर भारत का एक विशेष स्थान बना। वर्तमान में राजनीतिक कृपा प्राप्त अधिकारियों के कारण क्षीण होती जा रही है। आईएएस या अन्य सेवाओं के अधिकारी कार्यपालिका से सीधे जुड़े होते हैं। संसद के सचिवालय में उनकी नियुक्ति सत्ता के नियंत्रण का द्वार खोल देती है। धर्म व्यक्तिगत जीवन में अर्थोपार्जन एवं मानवीय गुणों के विकास से लेकर मोक्ष तक का मार्ग सिखाता है।

भावना धीरे-धीरे खत्म होती जा रही है। सांसदों के अधिकार सीमित होते जा रहे हैं। जिस तरह से नियम और कानून संसद में बनाए जा रहे हैं। हो-हल्ले के बीच कानूनों को पास किया जा रहा है। संसद के अधिकार सरकार के जिम्मे किये जा रहे हैं। संसदीय नियमों की अवहेलना हो रही है। बार-बार नियमों में संशोधन हो रहे हैं। जिसके कारण संसद, सांसदों, लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति की गरिमा भी तेजी के साथ कम होती जा रही है। यह स्थिति केवल सचिवालय का उल्लंघन है, बल्कि संसदीय समितियों की निष्पक्षता और उनकी स्वतंत्रता पर भी कुटाघात है। महासचिव जैसी पद पर बैठा अधिकारी सरकार से प्रभावित है। सरकार के कब्जे पर वह निर्णय कर रहा है।

संसद की रिपोर्टों को सरकार को लोक करता है, या रोकता है। सांसदों की टिप्पणियों को दबा रहा है। संसदीय प्रक्रियाओं को पक्षपातपूर्ण सरकार के दबाव में उनमें बदलाव कर रहा है। इससे संसद की स्वतंत्रता, सचिवालय के प्रति जवाबदेही, निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की शक्ति को कमजोर किया जा रहा है। वर्तमान स्थिति को देखते हुए यह आवश्यक हो गया है, संसद के भीतर की नियुक्तियों में पारदर्शिता एवं संवैधानिक अनुशासन की पुनर्स्थापना हो। सुप्रीम कोर्ट और संसद की आंतरिक समितियों को इस गंभीर उल्लंघन पर सज्जान लेना चाहिए। लोकतंत्र तभी जीवित रह सकता है, जब उसके स्तंभ स्वतंत्र और संवैधानिक मर्यादा के अधीन हों। पिछले एक दशक में सरकार द्वारा

बहुमत के आधार पर जिस तरह से संसद की कार्यवाही संचालित की जा रही है लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति आंध्र मूंदकर सरकार की बात को मानकर संसद की कार्यवाही को बहुमत के आधार पर चला रहे हैं। उसके परिणाम अब देखने को मिल रहे हैं। लोकसभा और राज्यसभा सचिवालय में सीआरपीएफ के जवानों की तैनाती हो गई है। लोकसभा और राज्यसभा के सचिवालय में कार्यपालिका के अधिकारियों कर्मचारियों की नियुक्ति की जा रही है। लोकसभा और राज्यसभा में तैनात सुरक्षा बल गृह मंत्रालय के अधीन आते हैं लोकसभा और राज्यसभा के महासचिव जैसे पद प्रशासनिक अधिकारियों के पास पहुंच गए हैं। जिनकी चाबी सरकार के पास होती है।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तीन डिफेंस पीएसयू को दिया मिनीरत्न का दर्जा

नई दिल्ली।

म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड (एमआईएल), आर्मड व्हीकल्स निगम लिमिटेड (एवीएनएल) और इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड (आईओएल) को मिनीरत्न श्रेणी-1 का दर्जा देने की मंजूरी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दी है। रक्षा मंत्री ने इन तीनों रक्षा सार्वजनिक उपक्रमों (डिफेंस पीएसयू) को सरकारी संगठन से लाभकारी कॉरपोरेट इकाई में तेजी से बदलने के लिए बधाई दी। उन्होंने कंपनी के टर्नओवर में वृद्धि, स्वदेशीकरण को

अधिकतम करने तथा अन्य प्रदर्शन मानकों को पूरा करने के लिए इनके प्रबंधन द्वारा उठाए गए कदमों की सराहना की। इन तीनों डिफेंस पीएसयू को मिनीरत्न का दर्जा मिलने से उन्हें अधिक स्वायत्तता, नवाचार और विकास की दिशा में सशक्त बनाने में मदद मिलेगी। म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड (एमआईएल) ने स्थापना के बाद से उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। कंपनी की वित्तीय वर्ष 2021-22 के 2,571.6 करोड़ रुपये से बढ़कर वित्त वर्ष 2024-25 में (अंतिम) 8,282 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है। निर्यात के क्षेत्र में

भी एमआईएल ने शानदार प्रगति की है। एमआईएल के प्रमुख उत्पादों में छोटे, मध्यम और उच्च कैलिबर के गोला-बारूद, मोर्टार, रॉकेट, हैंड ग्रेनेड आदि शामिल हैं, जिनका निर्माण इन-हाउस किया जाता है। आर्मड व्हीकल्स निगम लिमिटेड (एवीएनएल) ने भी उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की है। उसकी वित्तीय वर्ष 2021-22 के 2,569.26 करोड़ रुपये (2021-22) से बढ़कर 4,986 करोड़ रुपये (2024-25) (अंतिम) तक लगभग 190 प्रतिशत बढ़ी। एवीएनएल ने टी-72, टी-90 और बीएमपी-2 प्लेटफॉर्म के लिए

100 प्रतिशत स्वदेशी इंजन निर्माण हासिल किया है। इसके प्रमुख उत्पादों में टैंक्स (टी-90, अर्जुन, बीएमपी-2 सारथ), समर्थन वाहन और रक्षा मोबिलिटी समाधान शामिल हैं। इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड (आईओएल) ने भी पिछले तीन वर्षों में जबरदस्त प्रगति की है। कंपनी की वित्तीय वर्ष 2021-22 के 2,569.26 करोड़ रुपये (2021-22) से बढ़कर 1,541.38 करोड़ रुपये (2024-25) (अंतिम) हो गई है, जो 250 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि है। आईओएल के मुख्य उत्पादों में ऑप्टो-इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम और दृष्टि



उपकरण शामिल हैं, जिनका उपयोग टी-90, टी-72, बीएमपी-2 जैसे लड़ाकू प्लेटफॉर्म और तोपों, नौसेना के हथियारों आदि में होता है।



पटाखा फैक्ट्री में हुए धमाके से गिरी बिल्डिंग, 5 की मौत, कईयों के दबे होने की आशंका

चंडीगढ़।

पंजाब के मुक्तसर जिले में बड़ा हादसा हो गया है। खबर है कि एक पटाखा निर्माण इकाई की इमारत ढह गई है, जिसमें पांच मजदूरों की मौत हो गई है। यह हादसा धमाके के चलते हुआ था। फिलहाल, पुलिस मामले की जांच कर रही है। आशंका जताई जा रही है कि मलबे में कई और लोग दबे हो सकते हैं। राहत कार्य भी शुरू कर दिया गया है। मुक्तसर एसएसपी अखिल चौधरी ने कहा है कि मलबे से दो शव निकाले गए हैं और घायलों को बचाने की कोशिश लगातार की जा रही है। खबर है कि एम्स यानी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बटिंडा में करीब 20 मजदूरों को भर्ती कराया गया है। इसके अलावा मुक्तसर के कुछ अस्पतालों में भी मजदूरों के इलाज चल रहा है। एसएसपी ने कहा, शुरुआती जानकारी से पता चला है कि धमाका पटाखा निर्माण क्षेत्र में अज्ञात कारणों से हुआ था, जिसके कारण इमारत ढह गई। प्रथम दृष्टया लग रहा है कि मौतों फैक्ट्री ढांचा गिरने की वजह से हुई है ना कि आग के चलते। वहीं सूत्रों ने बताया कि घटना रात करीब 2 बजे घटी। हरियाणा राज्य की सीमा पर स्थित इस यूनिट में कर्मचारी पटाखा बनाने और उनकी पैकेजिंग का काम कर रहे थे। खास बात है कि इनमें से अधिकांश अग्रवासी हैं। जिला प्रशासन ने बचाव कार्य शुरू कर दिया है।

कानपुर पहुंचे पीएम मोदी ने शुभम द्विवेदी के परिवार से मुलाकात की

कानपुर (ईएमएस)। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी शुक्रवार को अपने कानपुर के दौरे के दौरान पहलगाम आतंकवादी हमले में मारे गए कारोबारी शुभम द्विवेदी के परिवार से मुलाकात की। जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने बताया, प्रधानमंत्री मोदी चकरी हवाई अड्डे पर उतरने के तुरंत बाद शुभम की पत्नी ऐशान्या, पिता संजय द्विवेदी और मां सीमा द्विवेदी से मुलाकात की। एक सप्ताह पहले कानपुर से सांसद रमेश अवस्थी ने प्रधानमंत्री कार्यालय को पत्र लिखकर प्रधानमंत्री से, पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए स्थानीय निवासी शुभम द्विवेदी के परिवार से मिलने का अनुरोध किया था। सांसद ने प्रधानमंत्री से 30 मई को कानपुर दौरे के दौरान शोकाकुल परिवार से मिलने का आग्रह किया था। अवस्थी ने कहा था कि उन्होंने प्रधानमंत्री कार्यालय को जो पत्र भेजा है, उसमें परिवार ने ऑपरेशन सिंदूर के लिए प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद दिया है। उनके अनुसार, दिवंगत कारोबारी के परिजन को लगता है कि आतंकी हमले के जवाब में भारत द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर से शुभम की आत्मा को शांति मिली होगी और इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री को धन्यवाद देने की इच्छा व्यक्त की है।

कार से मिले करीब डेढ़ करोड़ रुपये, व्यापारी दीपक खंडेलवाल को नोटिस

मथुरा।

यमुना एक्सप्रेस वे पर कार से मिले करीब डेढ़ करोड़ रुपये और साढ़े चार सौ ग्राम सोने के मामले में आयकर विभाग ने व्यापारी दीपक खंडेलवाल को नोटिस दे दिया है। इस बारे में दो दिन में जवाब मांगा है। बात दें कि माधव कुंज कॉलोनी, मसानी रोड निवासी खंडेलवाल सोने-चांदी की स्पलाई का व्यापार करता है। दीपक आगरा में सामान स्पलाई करने के बाद पेमेंट व बचा हुआ सोना लेकर अपनी कार से दिल्ली की ओर जा रहे थे। सूचना मिलने पर आयकर विभाग सक्रिय हुआ। आनन-फानन में थाना प्रभारी निरीक्षक मांट जसवीर सिंह और आयकर अधिकारी अपनी टीम के साथ यमुना एक्सप्रेस वे के मांट टोल प्लाजा पर वाहन चेकिंग में जुट गए। आयकर व पुलिस की संयुक्त टीम ने आगरा की ओर से आ रही स्विफ्ट कार को रोका गया। पूरी रात आयकर विभाग के अधिकारी खंडेलवाल से पूछताछ करते रहे लेकिन गाड़ी में मिले करीब डेढ़ करोड़ रुपये व 452 ग्राम सोने के बारे में दीपक कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे सका। इस पर टीम ने सोना व नकदी सीज कर दी। आयकर अधिकारी ने बताया कि बरामद रुपये व सोने को फिलहाल मांट पुलिस के सुपुर्द किया है और खंडेलवाल को नोटिस देकर बरामद रुपये व सोने के बाबत जवाब मांगा गया है।

बीजेपी के नए बॉस को लेकर जाने क्या आया अपडेट

नई दिल्ली।

भाजपा के लिए नए अध्यक्ष का इंतजार काफी लंबा हो गया है। आम चुनाव के करीब 1 साल बीतने के बावजूद भाजपा को अब तक नया अध्यक्ष नहीं मिल सका है। हालांकि, खबरें थी कि अप्रैल या मई महीने में भाजपा को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल सकता है। लेकिन भारत-पाकिस्तान तनाव के बीच इस लेकर निर्णय नहीं लिया जा सका। हालांकि, अब इस मामले में एक नया अपडेट सामने आया है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव जून के तीसरे या चौथे सप्ताह में हो सकता है। इसका मतलब साफ है कि जून के आखिर तक बीजेपी को नया बॉस मिल जाएगा। फिलहाल जेपी नहुवा राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उनका कार्यकाल 2020 से 2023 तक था। लेकिन कार्यकाल को लोकसभा चुनाव तक बढ़ाया गया। इसके बाद से लगातार अभी तक नहुवा का कार्यकाल बढ़ता रहा है। इसके बाद अब इसकी संभावना ज्यादा दिख रही है कि जल्दी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर निर्णय लिया जा सकता है। फिलहाल पार्टी राज्यों में संगठन को लेकर चुनाव कर रही है। इसके बाद 50 प्रतिशत राज्यों में संगठन चुनाव संपन्न हो जाने के बाद भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर प्रक्रिया शुरू कर सकती है। जानकारी के मुताबिक भाजपा चुनाव के दूसरे सप्ताह में राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम के लिए अधिसूचना जारी करेगी। राज्यों में संगठन आत्मक चुनाव संपन्न होने के बाद राष्ट्रीय स्तर पर चुनाव होने है। भाजपा अध्यक्ष पद की रेस में कई नाम सुर्खियों में हैं। हालांकि इस बार भाजपा का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा, उसके ऊपर 2029 आम चुनाव भी होगा। इसके अलावा बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, असम में महत्वपूर्ण विधानसभा चुनाव है जो भाजपा के लिए बेहद अहम है। इसके बाद पार्टी आगे किस तरीके की रणनीति बनाकर चलती है, यह भी देखने वाली बात होगी।

अब भारत नहीं आ पाएंगे पाकिस्तान के लोग, अफगानिस्तान की शुरु होगी आवाजाही

नई दिल्ली।

भारत सरकार ने न्यू अफगान वीजा मॉड्यूल के तहत जो सेवा शुरू की है, उसके अनुसार ऐसे लोगों को ही वीजा मिलेगा, जिन्हें किसी तरह का इलाज कराना हो या फिर मरीज की तीमारदारी करनी हो। वहीं छात्रों, कारोबारियों, मेडिकल अटेंडेंट, यूएन डिप्लोमेट वीजा पर आने वाले लोगों को भी एंटी दी जाएगी। इन वीजा के आवेदनों पर हर मामले को लेकर अलग-अलग फैसला लिया जाएगा। वहीं पहलगाम आतंकी हमले के बाद से पाकिस्तान के लोगों की एंटी पर भारत सरकार ने बैन लगा रखा है। वीजा सेवाएं ठप कर दी गई हैं। इस बीच तालिबान से भारत के रिश्तों में सुधार को देखते हुए

अफगानिस्तान के लोगों के लिए वीजा सेवाओं को शुरू किया गया है। बीते माह विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने अफगानिस्तान के अपने समकक्ष आमिर खान मुत्ताफी से बात की थी। वहीं तालिबान शासन ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले की निंदा की थी और कहा था कि इस लड़ाई में हम भारत के साथ हैं। दरअसल भारत और अफगानिस्तान के बीच चाबहार पोर्ट को लेकर भी सझेदारी है। वहीं इंटरनेशनल नार्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर को लेकर भी दोनों देश मिलकर काम कर रहे हैं। यह कॉरिडोर भारत से लेकर ईरान, रूस होते हुए यूरोप को जोड़ने वाला है। इस तरह दो अहम प्रोजेक्ट्स में दोनों देश साथ हैं और पाकिस्तान के साथ दोनों के

ही संबंध सहज नहीं हैं। अफगानिस्तान के लोगों को वीजा आवेदन करने के लिए मौके की एक तस्वीर, पासपोर्ट की डिटेल्स और एक अन्य आईडी कार्ड पोर्टल पर सबमिट करना होगा। यह फैसला महत्वपूर्ण है क्योंकि बीते कुछ महीनों में तालिबान के साथ भारत के रिश्ते सामान्य हुए हैं। तालिबान ने भारत को भरोसा दिया है कि उसकी जमीन से आतंकी गतिविधियों को संचालित नहीं होने दिया जाएगा। वहीं पाकिस्तान से उसके रिश्ते खैबर पख्तूनख्वा में सक्रिय आतंकीयों और ड्रग्स लाइन को लेकर सहज नहीं हैं। ऐसी स्थिति में भारत के साथ संबंध सुधार के अपने मायने हैं। भारत ने अफगानियों के लिए वीजा सेवा शुरू करके इसका संदेश भी दिया है।

आतंकवादी हमले के 96 घंटों के भीतर नौसेना ने कर ली थी पूरी तैयारी : राजनाथ सिंह

नई दिल्ली।

हाल ही में पाकिस्तान के साथ हुए सैन्य टकराव के दौरान भारत की तीनों सेनाओं ने अपने पराक्रम को दिखाया। जहां भारतीय वायुसेना ने हवा से पाकिस्तान पर कहर बरपाया। वहीं भारतीय नौसेना ने पानी के जरिए शिकंजा कस रखा था। भारत-पाकिस्तान के बीच सीजफायर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बार-बार कहा है कि ऑपरेशन

सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। इस बीच रक्षा मंत्री सिंह की एक तस्वीर सामने आई है। तस्वीर में रक्षा मंत्री सिंह भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल युद्धपोत आईएनएस विक्रान्त पर सवार दिख रहे हैं और फोटो में नौसेना के अधिकारी और जवान भी दिख रहे हैं। उन्होंने कहा, समुद्र में तैनात हमारे वेस्टर्न फ्लोटी शिप ने आतंकवादी हमले के 96 घंटों के भीतर, वेस्टर्न और ईस्टर्न कोस्ट पर सरफेंस टू सरफेंस और सरफेंस टू एअर मिसाइलें और

टारपीडो से कई सफल फायरिंग की। इस दौरान रक्षा मंत्री ने कहा, आईएनएस विक्रान्त पर अपने जांबाज नेवी के जवानों के बीच आकर मुझे खुशी हो रही है। मैं भारत की समुद्री शक्ति के गौरव आईएनएस विक्रान्त पर खड़ा हूँ, मेरे अंदर खुशी के साथ-साथ एक गर्व और विश्वास का भाव है, कि जब तक राष्ट्र की समुद्री सीमाओं की सुरक्षा आपके मजबूत हाथों में है, तब तक भारत को कोई तिरछी निगाहों से देख नहीं सकता।

उन्होंने कहा, आज मैं यहां केवल रक्षा मंत्री के नाते नहीं आया हूँ, बल्कि मैं यहां एक कुतूहल भारतीय के रूप में आया हूँ। मैं आपके समर्पण को नमन करने, आपके शौर्य को सराहने और आपके परिश्रम को सलाम करने आया हूँ। पाकिस्तान दुनिया के सामने किड़गिड़ाया

केंद्रीय रक्षा मंत्री सिंह ने कहा, मात्र कुछ ही समय में हमारी सेना ने पाकिस्तान के आतंकी अड्डे और उसके इरादों को ध्वस्त कर दिया।

दो राज्यों में बिछाई जाने वाले रेलवे लाइन से 784 गांव जुड़ेंगे और 20 करोड़ लीटर तेल बचेगा

नई दिल्ली।

भारतीय रेलवे ने 176 किलोमीटर नई रेल लाइन बिछाने का फैसला किया है, जिससे पर्यावरण और अर्थव्यवस्था को बड़ा फायदा होगा। इस कदम से हर साल 20 करोड़ लीटर तेल की खपत होगी और 99 करोड़ किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन घटेगा। यह 4 करोड़ पेड़ लगाने जितना असरदार है। भारतीय रेलवे मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में ऐसी जगह लाइन बिछाने जा रहा है, जिससे न सिर्फ वहां के लोगों को फायदा होगा बल्कि सालाना करोड़ों लीटर तेल की बचत

होगी। इसके साथ ही पर्यावरण भी संरक्षित करने में मदद करेगा। यह लाइन अगले पांच सालों में बनकर तैयार हो जाएगी और लोग इससे सफर कर सकेंगे। यह रेल लाइन महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में बिछाई जाएगी और अगले पांच साल में काम पूरा हो जाएगा। यानी 2030 तक पूरी हो जाएगी। इससे माल ढुलाई और यात्रियों की आवाजाही आसान होगी, साथ ही सामान पहुंचाने की लागत भी कम होगी। यहां पर दो लाइनें बिछेगी, पहली रतलाम-नागदा के बीच तीसरी और चौथी रेल लाइन और दूसरी वर्धा-बल्हारशाह के बीच चौथी रेल लाइन। इन परियोजनाओं की लागत करीब 3,399 करोड़

रुपये होगी। ये परियोजनाएं पीएम-गति शक्ति योजना का हिस्सा हैं, जो देश में यातायात और माल ढुलाई को बेहतर बनाने के लिए बनाई गई है। ये लाइनें 784 गांवों को जोड़ेंगी, जहां करीब 19.74 लाख लोग रहते हैं। ये रेल लाइनें कोयला, सीमेंट, कृषि उत्पाद, पेट्रोलियम और कटेनर जैसे सामानों की ढुलाई के लिए महत्वपूर्ण हैं। इनसे हर साल 18.40 मिलियन टन अतिरिक्त माल ढुलाई हो सकेगी। रेलवे पर्यावरण के लिए बेहतर और ऊर्जा बचाने वाला साधन है। यह तेल आयात और कार्बन उत्सर्जन कम करने में मदद करेगा, जिससे पर्यावरण को लाभ होगा।

टिकट मांगने वाले नेताओं को पीएम मोदी ने दी नसीहत कहा- जमींदारी प्रथा नहीं चलेगी

पटना।

बिहार दौरे पर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा के उन नेताओं को बड़ा इंटका दे दिया जो अपने बहु-बेटों के लिए टिकट की आस लगाए बैठे हुए थे। सूत्रों के मुताबिक उन्होंने सांसदों, विधायकों और पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक में लकीर खींचते हुए कहा कि राजनीति में परिवारवाद नहीं होना चाहिए, जमींदारी प्रथा नहीं होनी चाहिए। आप नहीं तो आपके पुत्र, यह नहीं होना चाहिए। उन्होंने टिकट बंटवारे में कार्यकर्ताओं को तरजीह देने की बात कही और सबालिया अंदाज में मौजूद नेताओं से यह भी कहा कि कार्यकर्ता मेहनत क्यों करता है? उसे मेहनत का फल क्यों नहीं मिलना चाहिए? पीएम मोदी ने

टिकट की दावेदारी कर रहे नेताओं को लेकर लकीर खींचते हुए कहा कि सोशल मीडिया पर ताकत होगी, तभी टिकट की दावेदारी होगी। नेताओं और कार्यकर्ताओं को सोशल मीडिया पर एक्टिव होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो भी नेता उम्मीदवारी (टिकट) चाहते हैं, सोशल मीडिया पर उनके कम से कम 50 हजार से अधिक फॉलोवर होने चाहिए। पीएम मोदी ने जीत का मंत्र देते हुए कहा कि बूथ मजबूत कीजिए। बूथ मजबूत होगा, तभी चुनाव जीतेंगे। बूथ जीतो, बिहार जीतो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी राज्य बिहार के दो दिवसीय दौरे के पहले दिन भाजपा के प्रदेश कार्यालय में सांसदों, विधायकों और पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक की। पटना स्थित बिहार बीजेपी के कार्यालय में करीब 70

मिनट तक चली इस बैठक में पीएम मोदी ने नेताओं से संवाद किया, आगामी बिहार चुनाव में जीत का मंत्र दिया। पीएम मोदी ने नेताओं को बीजेपी की अब तक की यात्रा और पूर्वजों के बलिदान को याद रखने की नसीहत दी और विधानसभा चुनाव से पहले टिकट बंटवारे को लेकर भी स्पष्ट लकीर खींच दी। बीजेपी सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पीएम मोदी ने इस बैठक में कहा कि बीजेपी चार पीढ़ी के बाद यहां तक पहुंची है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनी है। पूर्वजों के बलिदान याद रखिए, जिसके बाद हम आज यहां तक पहुंच पाए हैं। लोगों को जागरूक करिए-पीएम मोदी ने नेताओं से कहा कि सरकार का काम जनता के बीच लेकर जाए।

भारत करांची बंदरगाह पर हमले के लिए था तैयार, अमेरिका के आगे गिड़गिड़ाया पाक

भारतीय वायुसेना ने कई एयरबेस को कर दिया था तबाह

नई दिल्ली।

मई की रात भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध की आहट विश्व मंच तक पहुंच गई। सूत्रों के मुताबिक भारत के ऑपरेशन सिंदूर के जवाब में पाकिस्तान ने 'ऑपरेशन बनयान अल-मरसूस' नामक सैन्य कार्रवाई की शुरुआत की, लेकिन यह महज आठ घंटे में ही धराशायी हो गई। जवाबी कार्रवाई में भारत की वायुसेना ने पाकिस्तान के कई अहम सैन्य

ठिकानों को तबाही कर दिया। शतोंत भारतीय राफेल विमानों से मिसाइलें और एसयू-30 एमकेआई विमानों से ब्रह्मोस क्रूज मिसाइलें दागी गईं। हमलों में चकलाल में नूर खान एयरबेस, जैकोबाबाद और भोलाही एयरबेस को भारी नुकसान पहुंचा। नूर खान एयरबेस, पाकिस्तान की उत्तरी एयर कमांड के कमांड-कंट्रोल नेटवर्क का हिस्सा था और पहले ही हमले में ध्वस्त हो गया। मीडिया रिपोर्टों में वायुसेना के

पास मौजूद सबूतों के मुताबिक इन हमलों में पाकिस्तान के एक सी-130जे ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, एक जेएफ-17, और दो एफ-16 फाइटर जेट्स को मार गिराया गया। भारतीय एस-400 एयर डिफेंस सिस्टम, जो आदमपुर एयरबेस पर तैनात था, उसने इस ऑपरेशन में 11 बार दुश्मन के विमानों को रोका। इसने 315 किमी दूर पाकिस्तान की सीमा में उड़ रहे साब-2000 एयरबोन अल्टी वार्निंग सिस्टम को भी निशाना

बनाकर गिरा दिया। 10 मई को भारत ने लाहौर में तैनात चीनी एलवॉय-80 एयर डिफेंस सिस्टम को हारपेज कामिकेज ड्रोन से तबाह कर दिया। इसके अलावा करांची के मल्लो इलाके में तैनात पाकिस्तान के सीमा में उड़ रहे मिसाइल ने नष्ट कर दिया। ऑपरेशन की शुरुआत की थी और दावा किया था कि वह 48 घंटे में भारत के एयरबेस तबाह कर देगा, लेकिन भारतीय सेना के सटीक

और तीव्र प्रहार से पाकिस्तान की योजना परत पड़ गई। स्थिति जब हाथ से निकलने लगी तो पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत से सीजफायर की अपील की। सूत्रों के मुताबिक भारतीय नौसेना करांची बंदरगाह पर हमलों के लिए तैयार थी और उसका बेड़ा मकरान तट से महज 260 मील दूर था। पाकिस्तान ने चेतावनी दी, लेकिन भारत पीछे नहीं हटा। दोपहर तक पाकिस्तान ने युद्धविराम की आधिकारिक गृहण लगाई।

राष्ट्रपति मुर्मू ने गोवा की संस्कृति व विरासत के संरक्षण के लिए किया आह्वान

गोवा के स्थापना दिवस पर राज्यवासियों को दी शुभकामनाएं

पणजी।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शुक्रवार को गोवा के स्थापना दिवस के अवसर पर राज्यवासियों को शुभकामनाएं दीं और राज्य की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण में पर्यटन की भूमिका को रेखांकित किया। उन्होंने सतत पर्यटन (सस्टेनेबल टूरिज्म) को बढ़ावा देने की अपील करते हुए कहा कि गोवा की सुंदरता और विरासत को सुरक्षित रखने के लिए पर्यटकों और स्थानीय समुदायों को मिलकर काम करना होगा। राष्ट्रपति मुर्मू ने सोशल मीडिया

प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा, कि राज्य स्थापना दिवस पर गोवा के लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। गोवा की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, सुंदर समुद्र तट, गर्मजोशी से भरा आतिथ्य और अन्य कई आकर्षण दुनिया भर के पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। उन्होंने आगे कहा, पर्यटकों और स्थानीय निवासियों को राज्य की संस्कृति और विरासत को संरक्षित करने के लिए सतत पर्यटन को अपनाते हुए एक साथ आना चाहिए और स्थानीय समुदायों का सहयोग करना चाहिए। स्थापना दिवस का ऐतिहासिक

महत्व गौरतलब है कि 30 मई 1987 को गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। इससे पहले यह केंद्र शासित प्रदेश गोवा, दमन और दीव का हिस्सा था। राज्य बनने के बाद से गोवा ने आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति की है। विकसित भारत के निर्माण में गोवा का योगदान राष्‍ट्रपति मुर्मू ने अपने संदेश के अंत में कामना की, कि गोवा राज्य निरंतर प्रगति करे और विकसित भारत के निर्माण में सक्रिय योगदान देता रहे।

पहला कॉलम



छात्रों के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट का फैसला, नीट पीजी परीक्षा एक ही शिफ्ट में होगी

नई दिल्ली।

नीट पीजी परीक्षा एक ही शिफ्ट में आयोजित होगी। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को इसका आदेश दिया। छात्रों ने 2 शिफ्ट में परीक्षा के खिलाफ याचिका दाखिल की थी। याचिका दाखिल करने वाले छात्रों का कहना था कि 2 शिफ्ट में परीक्षा से मुख्य पेपर के डिफिकल्टी लेवल में फर्क होता है, जो फेयर इक्वैल यूपेशन नहीं है। परीक्षा में हासिल किए गए नंबरों में भी फर्क आ जाता है। दरअसल नीट पीजी ए जाम 15 जून को होना है जिसके लिए एडमिट कार्ड 2 जून को जारी होने है। इस कारण सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने मामले की जल्द द सुनवाई की है। बेंच ने कहा कि ये तर्क माना नहीं जा सकता कि ए जाम कराने के लिए एनबीई (नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन) को पर्याप्त त संतर नहीं मिले। 2 शिफ्ट में परीक्षा कराना ठीक नहीं है। दो पेपर्स का डिफिकल्टी लेवल कभी एक जैसा नहीं हो सकता। नॉर्मलाइजेशन का इस्तेमाल एके से शनल केसेज में होना चाहिए, न कि रूटिन परीक्षाओं में। इस साल का ए जाम 15 जून को होना है। अभी भी ए जामिनेशन बांडी तय करने और सेंटर्स चुनने के लिए 2 सप्ताह से ये याद का समय बाकी है। इसके बावजूद अगर और समय की जरूरत होती है, तब आवेदन कर सकते हैं।

खुलेआम ऑनलाइन सट्टेबाजी को प्रमोट कर रहे बल्लेबाज, बीसीसीआई पैसा कमाने में व्यस्त

फैंस और माता-पिता बीसीसीआई के नैतिकता पर उठा रहे सवाल

नई दिल्ली।

आईपीएल ने देशभर के लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया है, लेकिन इसके साथ ही ऑनलाइन सट्टेबाजी की एक चिंताजनक प्रवृत्ति युवाओं में देखने में मिल रही है। तथाकथित फैंटेसी प्लेटफॉर्म को अक्सर क्रिकेट के कुछ सबसे बड़े नाम सपोर्ट करते दिखते हैं, लेकिन इसका बुरा परिणाम भी देखने को मिला है। देश में कुछ माता-पिता इस बात को लेकर चिंतित हैं। वे भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) पर मामले में चुप्पी साधने का आरोप लगा रहे हैं। महानगरों से लेकर छोटे शहरों तक, किशोर और वयस्क आसानी से पैसा कमाने और मशहूर हस्तियों के विज्ञापन के भ्रम में उल्टनकर फैंटेसी गेमिंग इओर सट्टेबाजी एप का शिकार हो रहे हैं। इसका नतीजा साफ दिख रहा है, वित्तीय संकट, पढ़ाई में गिरावट और मानसिक स्वास्थ्य संबंधी बढ़ती परेशानियां। 55 वर्षीय दिल्ली निवासी मनीष एक पिता हैं। उन्होंने जब पता चला कि उनके 16 वर्षीय बेटे ने ऑनलाइन सट्टेबाजी में 50 हजार रुपये उड़ा दिए हैं, तब उसके मोबाइल फोन से ऐसी तीन फैंटेसी एप हटा दी। पिता का सवाल है, हमारे क्रिकेट हीरो इतनी खतरनाक चीज का प्रचार क्यों कर रहे हैं? यह दिल तोड़ने वाला है। उन्होंने कहा, बीसीसीआई पैसा कमाने में लगा हुआ है। उन्हें इस बात की परवाह नहीं कि हमारे बच्चों के साथ क्या हो रहा है। शीर्ष क्रिकेटर इन एप का प्रचार कर रहे हैं और बोर्ड उन्हें रोक नहीं रहा। इनमें से कुछ प्लेटफॉर्म प्रमुख टूर्नामेंट्स को स्पॉन्सर भी कर रहे हैं। हाल ही में हुए एक मैच में हिस्सा लेने वाले एक परिवार को यह देखकर हैरानी हुई कि कई दर्शक अपने फोन पर खुलेआम सट्टेबाजी एप का प्रचार कर रहे हैं। हमने किशोरों को कॉल पर, स्टैडियम से लाइव बेट लगाते देखा। कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने कभी-कभी आईपीएल जैसी लीग में अवैध सट्टेबाजी नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है, लेकिन अब ज्यादा बड़ा खतरा मोबाइल एप से है जो फैंटेसी गेमिंग की आड़ में खुलेआम काम करते हैं। आलोचकों का तर्क है कि दुनिया की सबसे धनी और सबसे प्रभावशाली क्रिकेट संस्था बीसीसीआई को इसकी नैतिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए। फिर भी बोर्ड की चुप्पी ने लोगों की चिंता को और बढ़ा दिया है, खासकर तब जब प्रमुख आईपीएल खिलाड़ी इन प्लेटफॉर्मों के विज्ञापनों में दिखाई दे रहे हैं।

देश में कोरोना के मामले बढ़े, एक दिन के नवजात की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव

नई दिल्ली।

देश में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। सक्रिय मामलों की संख्या शुक्रवार को 1828 पहुंच गई। गुजरात के अहमदाबाद में एक दिन के नवजात की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। जिसके बाद बच्चे को आईसीयू में रखा गया है। बीते सप्ताह बच्चे की मां भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई थी, हालांकि अब उनकी रिपोर्ट निगेटिव है। इसके अलावा 8 महिलाओं की एक बच्ची गुरुवार से ऑक्सीजन सपोर्ट पर है। वहीं, देश में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 15 हो गई है, इसमें सबसे ज्यादा 6 मौतें महाराष्ट्र में हैं। राज्य सरकार कोरोना के लिए इन्फ्लूएंजा और सांस से जुड़ी बीमारियों पर सवें करा रही है। उधर केरल में सक्रिय मामले 727 हो गए हैं। मुख्यमंत्री पिनारई विजयन ने



बताया कि राज्य में ओमिक्रॉन जेएन वैरिएंट एलएफ 7 के मामले आ रहे हैं। महाराष्ट्र में 9 हजार से ज्यादा कोविड टेस्ट महाराष्ट्र सरकार ने बताया कि गुरुवार को कोविड के 79 नए मामले सामने आए। जबकि मुंबई में जनवरी 2025 से अब तक कुल 379 केस मिले हैं। जनवरी और फरवरी में एक-एक, अप्रैल में चार और मई में 373 मरीज मिले।

सुप्रीम कोर्ट को मिले तीन नए जज, चीफ जस्टिस गवई ने दिलाई शपथ

कॉलेजियम ने की थी सिफारिश, अब न्यायाधीशों की संख्या 34 हुई

नई दिल्ली।

भारत के चीफ जस्टिस बीआर गवई ने शुक्रवार को जस्टिस एन वी अंजनिया, जस्टिस विजय बिशनोई और जस्टिस अतुल एस चंद्रकर को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई।

इसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या 34 हो गई है।

बता दें 29 मई को सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने इन तीनों जजों की नियुक्ति की सिफारिश की थी, जिसे बाद में केंद्र सरकार ने मंजूरी

दे दी थी। इस संबंध में केंद्र सरकार की तरफ से अधिसूचना भी जारी की गई थी।

न्यायमूर्ति एन वी अंजनिया पूर्व में कर्नाटक हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे।

न्यायमूर्ति विजय बिशनोई पूर्व में गुवाहाटी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और न्यायमूर्ति अतुल एस चंद्रकर पूर्व में बॉम्बे हाईकोर्ट के न्यायाधीश थे। जस्टिस अंजनिया का कार्यकाल 23 मार्च 2030 तक रहेगा जस्टिस बिशनोई का कार्यकाल 25 मार्च 2029 तक और जस्टिस चंद्रकर का कार्यकाल 7 अप्रैल, 2030 तक

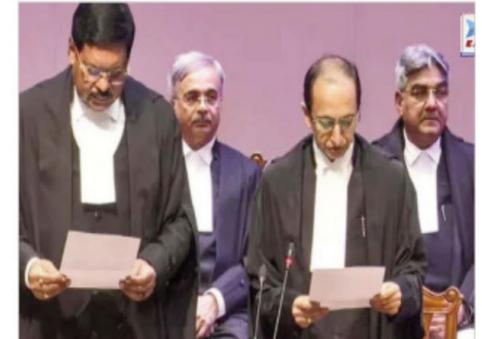
रहेगा।

न्यायमूर्ति अंजनिया का जन्म 23 मार्च, 1965 को अहमदाबाद में हुआ। उन्होंने 1989 में यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ लॉ, अहमदाबाद से कानून में मास्टर डिग्री हासिल की थी।

उन्होंने 1988 में गुजरात हाईकोर्ट में अपने वकालत के करियर की शुरुआत की। न्यायमूर्ति अंजनिया ने 25 फरवरी, 2024 को कर्नाटक हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली थी। इससे पहले उन्हें 21 नवंबर, 2011 को गुजरात हाईकोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में

नियुक्त किया गया था। इसके बाद छह सितंबर 2012 को उन्हें स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया।

26 मार्च, 1964 को जोधपुर में जन्मे न्यायमूर्ति विजय बिशनोई ने 1989 में वकालत शुरू की थी। बिशनोई ने 5 फरवरी 2024 को गुवाहाटी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। उन्हें 8 जनवरी, 2013 को राजस्थान हाईकोर्ट का अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया। इसके बाद 7 जनवरी, 2015 को उन्होंने हाईकोर्ट के स्थायी न्यायाधीश के रूप में शपथ ली।



जस्टिस एस चंद्रकर का जन्म 7 अप्रैल 1965 को हुआ था। कानून की डिग्री हासिल करने के बाद वे 21 जुलाई, 1988 को

बार में शामिल हुए थे। इसके बाद वे 1992 में अदालत चले गए, जहां उन्होंने कई अदालतों में वकालत की।

अमित शाह के दौरे के बीच कश्मीर में बड़ी कार्रवाई, टेरर नेटवर्क पर सीआईके ने कसा शिकंजा

श्रीनगर।

गृह मंत्री अमित शाह के दो दिवसीय जम्मू-कश्मीर दौरे के बीच घाटी में आतंकवाद के खिलाफ सुरक्षा एजेंसियों की ओर से बड़े पैमाने पर कार्रवाई देखने को मिली है। अमरनाथ यात्रा से पहले सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा के लिए श्रीनगर पहुंचे गृह मंत्री के दौरे के समानांतर, कश्मीर पुलिस की काउंटर-इंटेलिजेंस (सीआईके) यूनिट ने पुलवामा, शोपिया, बडगाम, श्रीनगर और बारमूला में आतंकवादी नेटवर्क से जुड़े संदिग्धों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की।

सीआईके द्वारा जारी बयान के अनुसार, ये अभियान आतंकवादी संगठनों के साथ कथित संबंध रखने वाले व्यक्तियों की पहचान और नेटवर्क को ध्वस्त करने की व्यापक रणनीति का हिस्सा था। इन छापों के दौरान मोबाइल फोन, सिम कार्ड, मेमोरी कार्ड सहित कई संदिग्ध डिजिटल साक्ष्य बरामद किए गए। साथ ही शोपिया जिले के सैदपुरा क्षेत्र से 18 वर्षीय युवक को गिरफ्तार

किया गया है।

23 मई को हुई थी एसआईके की बड़ी कार्रवाई

इससे पहले 23 मई को राज्य जांच एजेंसी (एसआईके) ने जम्मू प्रांत के चार जिलों में 18 स्थानों पर छापेमारी की थी। इस दौरान बड़ी मात्रा में आपत्तिजनक सामग्री जब्त की गई थी। ये छापेमारी स्लीपर सेल्स को निष्क्रिय करने और टेरर इकोसिस्टम को तोड़ने के लिए की गई थी।

गृह मंत्री की उच्चस्तरीय सुरक्षा बैठक अमित शाह के दौरे को ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद बेहद अहम माना जा रहा है। राजभवन पहुंचने के तुरंत बाद उन्होंने जम्मू-कश्मीर की समग्र सुरक्षा स्थिति और आतंकवाद रोधी अभियानों को लेकर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की भी समीक्षा की गई।

पुछ मंत्री जाएंगे शाह, शहीदों को देगे श्रद्धांजलि

गृह मंत्री शाह अपने दो दिवसीय दौरे के दौरान पुंछ जिले का भी दौरा करेंगे। पुंछ वह इलाका है



जहां 7 से 10 मई के बीच पाकिस्तानी गोलाबारी और ड्रोन हमलों में 14 नागरिकों समेत 28 लोगों की मौत हुई थी। वहां वे स्थानीय लोगों से मुलाकात कर सुरक्षा हालात का जायजा भी लेंगे।

सुरक्षा एजेंसियां सतर्क

इन कार्रवाइयों से साफ है कि केंद्र सरकार और जम्मू-कश्मीर प्रशासन आतंकवाद और उसके नेटवर्क के खिलाफ किसी भी तरह की नरमी बरतने के मूड में नहीं है। घाटी में चल रहे इन समन्वित अभियानों का उद्देश्य अमरनाथ यात्रा से पहले क्षेत्र को पूरी तरह सुरक्षित बनाना और आम नागरिकों में विश्वास कायम करना है।

भारत में 30 सालों तक सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बने रहने की क्षमता

केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने एक कार्यक्रम में रखे विचार

नई दिल्ली।

केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत एक आकर्षक निवेश गंतव्य है और अगले 30 सालों तक दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली बड़ी अर्थव्यवस्था बने रहने की क्षमता रखता है। उन्होंने कहा कि देश ने 6-7 फीसदी की निरंतर वृद्धि दर बनाए रखी है और स्थिर कीमतों पर इसे 8 फीसदी तक ले जाने की उम्मीद है।

उन्होंने कहा कि आज भारत के पास दुनिया का चौथा सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार है, जो करीब 690 अरब डॉलर है। पिछले तीन महीनों से हमारी मुद्रास्फीति 4 फीसदी से नीचे बनी हुई है। रिजर्व बैंक ने लिक्विडिटी और मुद्रा प्रबंधन को संतुलित करने में सराहनीय भूमिका निभाई है। केंद्रीय मंत्री ने भारत को एक

आकर्षक निवेश गंतव्य के रूप में उजागर किया। उन्होंने कहा कि पिछले 20-25 सालों में भारतीय कंपनियों ने लगभग 20 फीसदी सीएजीआर का रिकॉर्ड दिया है, जिससे भारत एक अहम निवेश गंतव्य बन गया है। हम अंतरराष्ट्रीय व्यापार संबंधों के माध्यम से विकास पथ पर वापस आ गए हैं।

उन्होंने विभिन्न मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) पर प्रगति की जानकारी दी, जिसमें यूईई, ऑस्ट्रेलिया, यूके, चार ईएफटीए देश और अमेरिका के साथ चल रहे द्विपक्षीय व्यापार समझौते की वार्ता भी शामिल है। उन्होंने कहा कि हम अमेरिका के साथ अपने द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर आगे बढ़ रहे हैं और यूरोपीय संघ के 27 देशों के समूह के साथ प्रगति कर रहे हैं। हमने न्यूजीलैंड के साथ भी बातचीत शुरू की है।

ईएफटीए देशों ने अगले 15 सालों में भारत में 100 अरब डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश करने की प्रतिबद्धता जताई है।

इसके कुल 500 अरब डॉलर के निवेश में तब्दील होने की उम्मीद है। इसके अलावा इस निवेश के इर्द-गिर्द जो बड़ा इकोसिस्टम बनाया जाएगा, उसमें 500 अरब डॉलर अतिरिक्त आकर्षित करने की क्षमता है। गोयल ने कहा कि हम छोटे लक्ष्य नहीं रख रहे हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इस आंकड़े में नॉर्वेजियन पेंशन फंड से निवेश शामिल नहीं है। उन्होंने कहा कि यह दुनिया का पहला मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) है। उन्होंने भारत की निरंतर आर्थिक प्रगति पर गर्व व्यक्त किया और कहा कि आईएमएफ ने अनुमान लगाया है कि 2027 तक भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी जीडीपी होगी।

गोल्ड लोन को लेकर नए नियम छोटे ग्राहकों को ना

नई दिल्ली।

वित्त मंत्रालय ने कहा कि उसने भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) सोना गिरवी रखकर कर्ज लेने वालों के हितों की रक्षा के लिए मानदंडों और तौर-तरीकों से संबंधित दिशानिर्देशों पर गौर किया है। यह निर्देश छोटे कर्जदारों को आरबीआई के प्रस्तावित नियमों से बाहर रखने के लिए सलाह देते हैं। इस निर्देश को लेकर तमिलनाडु में राजनीतिक दलों के विरोध के बावजूद वित्त मंत्रालय ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर जानकारी दी कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसके लिए मार्गदर्शन दिया है। डीएफएस ने भी केंद्रीय बैंक को छोटे स्वर्ण ऋण लेने वालों की आवश्यकताओं का विचार करने की सलाह दी है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने भी इस मुद्दे पर भारतीय रिजर्व बैंक को नए दिशा-निर्देशों में प्रस्तावित प्रतिबंधों पर पुनर्विचार करने की सलाह दी है। इसके बावजूद आरबीआई ने मसौदे में कहा है कि ऋणदाताओं को उपयुक्त नियमों का पालन करना होगा और सुनिश्चित करना होगा कि सीमित स्वर्ण ऋण लेने वालों की आवश्यकताओं का ध्यान दिया जाए। इसके साथ ही नीति निर्धारित सभी प्रक्रियाओं का विवरण ऋणदाताओं के लिए उपलब्ध होना चाहिए।

बिहार में कार्यक्रम के दौरान किसानों का हंगामा, जमीन अधिग्रहण का उचित मुआवजा नहीं मिलने का आरोप

पटना।

पटना के फतुहा स्थित सुकुलपुर गांव में कार्यक्रम के दौरान किसानों ने जमीन अधिग्रहण मुआवजे को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। यह कार्यक्रम प्रधानमंत्री द्वारा विक्रमगंज से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बिहार में 48,500 करोड़ रुपये की योजनाओं के शिलान्यास के लिए हुआ था। कार्यक्रम में भाजपा नेता और पूर्व सांसद रामकृपाल यादव ने 1083 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित होने वाली रामनगर-कच्ची दरगाह खंड की 14.5 किलोमीटर सिक्स लेन सड़क का शिलान्यास किया। तभी मौजूद किसान उग्र हो गए और कार्यक्रम स्थल से बाहर आकर प्रदर्शन करने लगे। किसानों का कहना था कि सरकार उनकी जमीन का जबरन अधिग्रहण कर रही है। उन्हें निर्धारित सरकारी दर का चौगुना मुआवजा नहीं मिल रहा है। किसान महीनों से इस मांग को लेकर संघर्षित हैं। स्थानीय नेताओं जैसे पूर्व मुखिया देवकुमार सिंह, अभिन्मयु यादव, इंजीनियर गोपाल शंकर और नरेशचंद्र यादव के समझाने पर किसान शांत हुए। रामकृपाल ने किसानों की मांगों को संबंधित वरिय अधिकारियों तक पहुंचाने का आश्वासन दिया। कार्यक्रम में पटना सिटी एसडीओ सत्यम सहाय, एनएचआई प्रबंधक अतुल पुंडीर, कार्यपालक अभियंता आलोक कुमार ठाकुर समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

कार से मिले करीब डेढ़ करोड़ रुपये, व्यापारी दीपक खंडेलवाल को नोटिस

मथुरा।

यमुना एक्सप्रेस वे पर कार से मिले करीब डेढ़ करोड़ रुपये और साढ़े चार सौ ग्राम सोने के मामले में आयकर विभाग ने व्यापारी दीपक खंडेलवाल को नोटिस दे दिया है। इस बारे में दो दिन में जवाब मांगा है। बात दें कि माधव कुंज कॉलोनी, मसानी रोड निवासी खंडेलवाल सोने-चांदी की सत्ताई का व्यापार करता है। दीपक आगरा में सामान सत्ताई करने के बाद पेटेंट व बचा हुआ सोना लेकर अपनी कार से दिल्ली की ओर जा रहे थे तब मथुरा में पर आयकर विभाग सक्रिय हुआ। आनन-फानन में थाना प्रभारी निरीक्षक मांत जसवीर सिंह और आयकर अधिकारी अपनी टीम के साथ यमुना एक्सप्रेस वे के मांट टोल प्लाजा पर वाहन चेकिंग में जुट गए। आयकर व पुलिस की संयुक्त टीम ने आगरा की ओर से आ रही रिवायट कार को रोक लिया। पुरी रात आयकर विभाग के अधिकारी खंडेलवाल से पूछताछ करते रहे लेकिन गाड़ी में मिले करीब डेढ़ करोड़ रुपये व 452 ग्राम सोने के बारे में दीपक कोई सतोषजनक जवाब नहीं दे सका। इस पर टीम ने सोना व नकदी सीज कर दी। आयकर अधिकारी ने बताया कि बरामद रुपये व सोने को फिलहाल मांट पुलिस के सुपुर्द किया है और खंडेलवाल को नोटिस देकर बरामद रुपये व सोने के बाबत जवाब मांगा गया है। जवाब मिलने के बाद आगामी कार्रवाई होगी। आयकर विभाग से मिले इनपुट के आधार पर पुलिस टीम ने एक्सप्रेस वे से काफी नकदी व सोना व्यापारी की कार से बरामद किया।